



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937

No. 203]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015 /CHAITRA 11, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

सं. 19/2015 सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 255(अ). – सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, उन सामग्रियों को, जिनका आयात विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.25 और 4.27 की दृष्टि से क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त प्राधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रति भारत में किया गया हो, एतद्वारा, उस पर लगने वाले उस संपूर्ण सीमा-शुल्क से जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है, यथा:-

(i) यह कि निकासी के समय उक्त प्राधिकार को सीमा-शुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष नामे (डेबिट) करने के लिए प्रस्तुत किया जाए;

(ii) यह कि उक्त प्राधिकार में निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) संख्या, निर्यातित परिणामी उत्पाद का विवरण, मात्रा तथा फ्री आन बोर्ड मूल्य तथा शिपिंग बिल संख्या और तारीख का पृष्ठांकित किया जाए;

बशर्ते कि उक्त सिओन वास्तविक उपयोक्ता शर्त का निर्धारण नहीं करता है;

(iii) यह कि आयात की गई सामग्री का विवरण और अन्य विशिष्टताएं जहां कहीं लागू होती हैं, मूल्य तथा मात्रा का उक्त प्राधिकार में उल्लेख किया गया है तथा आयात की गई सामग्री का मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हो;

बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 (i) तथा 4.12 (ii) में संदर्भित निविष्टि के संबंध में उक्त प्राधिकार में आयात के लिए मंजूर की सामग्री क्रमशः उसी विशिष्ट नाम/विवरण अथवा मात्रा की होगी जैसे कि

परिणामी उत्पाद के निर्यात में प्रयुक्त सामग्री है। निर्यातकर्ता प्रयुक्त की गई सामग्री के इन विवरणों की उद्घोषणा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में करेगा:

बशर्ते और भी कि उन परिणामी उत्पादों के संदर्भ में जिनके विनिर्माण के लिए उन निविष्टियों की आवश्यकता पड़ती है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.30 में विनिर्दिष्ट है, उक्त प्राधिकार में अनुमत सामग्री उसी गुणवत्ता, तकनीकी प्रकृति और विनिर्देशन की होंगी, जैसा कि परिणामी उत्पाद में प्रयुक्त सामग्रियां होती है. निर्यातक शिपिंग बिल में अथवा निर्यात बिल में प्रयुक्त सामग्री की उपरोक्त विशेषताओं के बारे में घोषणा करेगा;

(iv) यह कि उक्त प्राधिकार विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन हस्तांतरणीय होगा;

(v) यह कि आयात और निर्यात उन समुद्री बंदरगाहों, विमानपत्तनों अथवा इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा उन भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के जरिए से जिनका उल्लेख दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/2015 - सीमा-शुल्क की सारणी 2 में किया गया है अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं:

बशर्ते कि सीमा-शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा-शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

(vi) कि ऐसे परिणामी उत्पादों का निर्यात करके, जो कि भारत में विनिर्मित हों, जो कि उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट हो, उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट निर्यात को (मूल्य और मात्रा दोनों की दृष्टि से) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.29 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पूरा किया गया हो:

बशर्ते कि इन्डरमीडिएट आपूर्ति के प्राधिकार के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.05 (ग) (ii) के अनुसार निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात संबंधी दायित्वों को निभाया जा सकता है;

(vii) कि आयातकर्ता निर्यात संबंधी दायित्वों के निर्वहन का साक्ष्य उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उसकी संतुष्टि के लिए, प्रस्तुत करता है;

(viii) यह कि किसी व्यापारी निर्यातक को जारी उक्त प्राधिकार के संबंध में, उस सहायक विनिर्माता का, जो कि निर्यातित उत्पाद का विनिर्माण करता है, का नाम और पूरा डाक पता का शिपिंग बिल में घोषणा की जाये और उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(2) जहां कि सामग्री दोषपूर्ण या प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पायी जाती है वहां उस सामग्री को निकासी की तारीख से छह माह के भीतर या ऐसी बड़ी हुई अवधि जो और छह माह से अधिक न हो जैसा आयुक्त सीमा शुल्क अनुमति प्रदान करें विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस निर्यात की जा सकती है:

बशर्ते कि ऐसी सामग्री के वापस निर्यात करते समय उपायुक्त सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की संतुष्टि में यह पहचान हो कि यह वही सामग्री है जिसका कि आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए,-

(i) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(ii) "विनिर्माण" का वही अभिप्राय है जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.31 में दिया गया है;

(iii) "सामग्री" से अभिप्राय निम्न से है,-

(क) कच्चे माल, घटक, मध्यवर्ती, उपभोग योग्य, उत्प्रेरक या उस भाग से है जो परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी होते हैं;

(ख) (ख) पैकेजिंग सामग्री जो कि परिणामी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए जरूरी है;

"क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

[फा. सं. 605/55/2014-डी बी के]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2015

No. 19/2015 – Customs

G.S.R. 255(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against a valid Duty Free Import Authorisation issued by the Regional Authority in terms of paragraphs 4.25 and 4.27 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said authorisation) from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), subject to the following conditions, namely :-

(i) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(ii) that Standard Input Output Norms (SION) number, description, quantity and Free on Board value of the resultant product exported and the shipping bill number(s) and date(s) are endorsed on the said authorisation:

Provided that the said SION does not prescribe the actual user condition;

(iii) that the description and other specifications wherever applicable, value and quantity of materials imported are mentioned in the said authorisation and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorisation:

Provided that in respect of inputs referred in paragraphs 4.12(i) and 4.12(ii) of the Foreign Trade Policy, the material permitted to be imported in the said authorisation shall be of the specific name/description or quantity, respectively, as the material used in the export of the resultant product. The exporter shall declare these particulars of materials used in the shipping bill/ bill of export:

Provided further that in respect of resultant products requiring inputs specified in paragraph 4.30 of the Foreign Trade Policy, the materials permitted in the said authorisation shall be of the same quality, technical characteristics and specifications as the materials used in the said resultant product. The exporter shall declare these particulars of materials used in the shipping bill or bill of export;

(iv) that the said authorisation shall be transferable subject to such conditions as may be specified;

(v) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No.16/ 2015- Customs dated 01.04.2015 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(vi) that the exports as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) were fulfilled within the period specified in paragraph 4.29 of the Foreign Trade Policy by exporting resultant products, manufactured in India, which are specified in the said authorisation:

Provided that in case of an authorisation for intermediate supply, the export obligation shall have been discharged by supplying the resultant products to the exporter in terms of paragraph 4.05 (c) (ii) of the Foreign Trade Policy;

(vii) that the importer produces evidence of fulfillment of the export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;

(viii) that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter, the name and complete postal address of the supporting manufacturer who manufactured the export product is declared in the shipping bills and specified in the said authorisation.

2. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within six months from the date of clearance of the said material or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export, the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

Explanation – For the purposes of this notification,-

(I) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015 as amended from time to time;

(II) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.31 of the Foreign Trade Policy;

(III) "Materials" means,-

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;

(b) packaging materials required for packing of resultant product;

(IV) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation under the said Act.

[F. No. 605/55/2014-DBK]
SANJAY KUMAR, Under Secy.